ADVOCATE, RANJANA DIXIT
NATIONAL JOINT SECRETARY
GENERAL CELL (IN)

HELPLINE: +91 8510888811
E-MAIL: INFO@WHRRC.ORG
MEMBERSHIP ID: 0000003124

WORLD HUMAN RIGHTS RESEARCH COUNCIL (WHRRC)

DEDICATED TO HUMAN RIGHTS

SR NO: 0107082026 **DATE: 07 AUG 2026**

अनुशासनात्मक समिति गठन संबंधी सूचना

विश्व मानवाधिकार अनुसंधान परिषद्, राष्ट्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 01 अगस्त 2026 को जारी कारण बताओ नोटिस क्रमांक 0101082026 के माध्यम से राष्ट्रीय समिति एवं समस्त राज्य समितियों के पदाधिकारियों से तीन प्रमुख बिंदुओं पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त नोटिस के अनुपालन हेतु अंतिम समय-सीमा दिनांक 05 अगस्त 2026, सायं 05:00 बजे निर्धारित की गई थी।

निर्धारित अवधि के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा तीनों बिंदुओं पर क्रमवार, संतोषजनक एवं तथ्यपरक उत्तर प्रस्तुत न किए जाने के कारण संबंधित राष्ट्रीय एवं राज्य समिति के समस्त पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि के दौरान संबंधित पदाधिकारी निम्न अधिकारों एवं सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकेंगे—

1. संगठन के किसी भी पद का उपयोग अथवा दावा।
2. संगठन के नाम, लोगो एवं पहचान का किसी भी रूप में उपयोग।
3. संगठन द्वारा जारी आईडी कार्ड, लेटरहेड, विजिटिंग कार्ड, बैनर, वाहन स्टिकर, सोशल मीडिया प्रोफाइल डीपी अथवा अन्य किसी आधिकारिक सामग्री का उपयोग।
4. संगठन द्वारा आयोजित किसी भी बैठक, प्रशिक्षण, अभियान, कार्यक्रम अथवा अन्य आधिकारिक गतिविधि में पदाधिकारी के रूप में सहभागिता।

साथ ही, निलंबित पदाधिकारियों का विवरण संगठन की आधिकारिक वेबसाइट से अस्थायी रूप से हटा दिया गया है।

उक्त प्रकरण के निष्पक्ष परीक्षण एवं अंतिम अनुशासनात्मक निर्णय हेतु राष्ट्रीय कार्यालय द्वारा निम्नानुसार अनुशासनात्मक समिति का गठन किया जाता है—

अध्यक्ष

- डॉ. आर. एस. चौहान — राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार एवं सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता

पैनल सदस्य

- अधिवक्ता श्री विजय कुमार राय — राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार एवं सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता
- अधिवक्ता श्रीमती रंजना दीक्षित — राष्ट्रीय संयुक्त सचिव एवं हाईकोर्ट अधिवक्ता
- अधिवक्ता श्री भारत कुलकर्णी — राष्ट्रीय अध्यक्ष (फ़ूड सेफ्टी सेल)
- श्री अशोक कुमार योगी — राष्ट्रीय अध्यक्ष (सामाजिक न्याय सेल)

उक्त समिति प्रत्येक संबंधित पदाधिकारी का व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित करेगी तथा कारण बताओ नोटिस के तीनों बिंदुओं पर प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्षात्कार के दौरान दिए गए उत्तरों का परीक्षण करेगी।

समिति के समक्ष प्रत्येक पदाधिकारी को यह अवसर प्रदान किया जाएगा कि वह यह स्पष्ट एवं प्रमाणित कर सके कि उसे उसके वर्तमान पद से क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए। यदि अनुशासनात्मक समिति उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर यह संतुष्ट होती है कि संबंधित पदाधिकारी को पद से हटाया जाना उचित नहीं है, तो वह राष्ट्रीय कार्यालय को उसके पद को यथावत बनाए रखने अथवा आवश्यकतानुसार पुनः सक्रिय करने संबंधी अनुशंसा प्रस्तुत कर सकेगी।

इसी प्रकार, यदि समिति यह पाती है कि संबंधित पदाधिकारी अपने उत्तरों एवं साक्ष्यों से स्वयं को संतोषजनक रूप से सिद्ध करने में असफल रहा है, तो वह पद परिवर्तन, पदमुक्ति अथवा सामान्य सक्रिय सदस्य के रूप में रखने सहित आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा राष्ट्रीय कार्यालय को करेगी।

अगर **कोई** पदाधिकारी अनुशासनात्मक समिति के समक्ष ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, ऑडियो या **वीडियो** कॉल द्वारा प्रस्तुत नहीं **होता है**, तो उस स्थिति में यह **मान** लिया जाएगा **कि** वह अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करने में **रुचि** नहीं **रखता है।** इस **स्थिति** में दिनांक 10 अगस्त **2026** के बाद उसे स्वतः ही **एक्टिव मेंबर** के पद पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

साक्षात्कार के लिए उक्त सभी निलंबित पदाधिकारी दिनांक 06 अगस्त 2026 से दिनांक 10 अगस्त 2026, शाम 5 बजे तक (सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक) अनुशासनात्मक समिति के अध्यक्ष डॉ. आर. एस. चौहान से सामान्य कॉल द्वारा मोबाइल नंबर **9205109288** पर संपर्क कर सकते **हैं।**

अनुशासनात्मक समिति अपनी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 10 अगस्त 2026, रात्रि 10:00 बजे तक अपनी अंतिम जांच एवं अनुशंसा रिपोर्ट राष्ट्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेगी। समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत राष्ट्रीय कार्यालय द्वारा अंतिम निर्णय पारित किया जाएगा, जो संबंधित सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

भवदीया,

अधिवक्ता, रंजना दीक्षित
राष्ट्रीय संयुक्त सचिव
विश्व मानवाधिकार अनुसंधान परिषद्, दिल्ली

SR NO: 0105082026 **DATE: 05 AUG 2026**

Notice Regarding the Constitution of the Disciplinary Committee

The National Office of the World Human Rights Research Council, through Show Cause Notice No. **0101082026** dated **01 August 2026**, directed the office bearers of the National Committee and all State Committees to submit their explanations on three major points. The final deadline for compliance with the said notice was fixed as **05 August 2026 at 05:00 PM**.

As the explanations were either not submitted within the stipulated period or satisfactory, factual, and point-wise replies to all three issues were not furnished, all concerned office bearers of the National Committee and the respective State Committees are hereby placed under **temporary suspension with immediate effect**.

During the period of suspension, the concerned office bearers shall not be entitled to exercise or use the following rights and privileges:

1. To hold, claim, or exercise any office or designation within the organization.
2. To use the name, logo, or identity of the organization in any manner whatsoever.
3. To use any official materials issued by the organization, including Identity Cards, Letterheads, Visiting Cards, Banners, Vehicle Stickers, Social Media Profile Display Pictures (DPs), or any other official material.
4. To participate, in the capacity of an office bearer, in any meeting, training programme, campaign, event, or any other official activity organized by the organization.

Furthermore, the details of the suspended office bearers have been temporarily removed from the official website of the organization.

For the purpose of conducting an impartial examination of the matter and making a final disciplinary recommendation, the National Office hereby constitutes the following Disciplinary Committee:

Chairperson

- **Dr. R. S. Chauhan** — National Legal Advisor & Advocate, Supreme Court of India

Panel Members

- **Advocate Mr. Vijay Kumar Rai** — National Legal Advisor & Advocate, Supreme Court of India
- **Advocate Mrs. Ranjana Dixit** — National Joint Secretary & Advocate, High Court
- Advocate Mr. Bharat Kulkarni — National President (Food Safety Cell)
- Mr Ashok Kumar Yogi — National President (Social Justice Cell)

The Committee shall conduct an individual interview of each concerned office bearer and examine the explanations submitted in response to the three points mentioned in the Show Cause Notice, along with the available records and the responses provided during the interview.

Each office bearer shall be afforded an opportunity before the Committee to clearly establish, with supporting evidence, why he or she should not be removed from the present office. If, on the basis of the facts and evidence available, the Disciplinary Committee is satisfied that the concerned office bearer should not be removed from office, it may recommend to the National Office that the office be retained as it stands or reactivated, as may be considered appropriate.

Similarly, if the Committee finds that the concerned office bearer has failed to satisfactorily establish his or her position through the explanations and supporting evidence, it shall recommend appropriate disciplinary action to the National Office, including change of office, removal from office, or continuation only as an Active Member.

If any office bearer fails to appear before the Disciplinary Committee through an online conference, audio call, or video call, it shall be presumed that he or she is not interested in discharging the responsibilities of the assigned office. In such a case, after **10 August 2026**, the concerned individual shall automatically be transferred to the position of **Active Member**.

For the interview, all the suspended office bearers may contact **Dr. R. S. Chauhan**, Chairperson of the Disciplinary Committee, through a normal phone call on **Mobile No. 9205109288**, between **06 August 2026 and 10 August 2026**, up to **05:00 PM**, during the hours of **10:00 AM to 08:00 PM**.

The Disciplinary Committee shall complete all proceedings and submit its final inquiry and recommendation report to the National Office by **10 August 2026 at 10:00 PM**. Upon receipt of the Committee's recommendations, the National Office shall pass the final decision, which shall be binding upon all concerned parties.

Yours faithfully,

Advocate, Ranjana Dixit
National Joint Secretary
World Human Rights Research Council, Delhi